RAJYA SABHA

Monday, the ISth December, 1972/27ih Agmhgyana, 1894 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock. MR CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

706. *[The questioners (Shri V. K. Sakhalecha, Shri Lai K. Advani, Shri D. K. raid, Shri Jagdish Prasad Malhur, Shri Rattan Lai Iain, Shri N. K. Shejwalkar) were absent. For answer* vide *cols.* 37—39 infni.]

707. *[The questioner (Shri M. K. Mohta) was absent. For answer* vide *col.* 40 infra,]

708. *[The questioner (Shri O.* P. *Tyai-i) was absent. For answer the* vide *col.* 40 infra.]

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा वैगनों को रोक कर रखा जाना

*709. डा० भाई महावीर :†
श्री मान सिंह वर्मा :
श्री रत्तन लाल जैन :
श्री श्रोम्म प्रकाश त्यागी :
श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल के डिब्बों को निर्धारित समय से अधिक समय तक रोक कर रखने के कारण गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उप-क्रमों से कुल कितनी राशि डैमरेज के रूप में वसूल की गयी; और

(ख) इस प्रकार अनावश्यक रूप से डिब्बों को रोके रखना कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं?

.^[DETENTION or WAGONS BY INDUSTRIES IN PUBLIC SECTOR

709. DR. BHAI MAHAVIR:
SHRI MAN SINGH VARMA:
SHRI RATTAN LAL IAIN:
SHRI O. P. TYAGI:
SHRI V. K. SAKHALECHA:
SHRI J. P. YADAV:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total amount of demurrage charged from the industries and undertakings in public sector during the last three years on account of detention of wagons for more than the specified time; and

(b) the steps that have been taken to minimise such unnecessary detention and the results thereof?]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) The total amount of demurrage charges realised from the industries and undertakings in public sector during the last three years is as under;—

1969-70	...	Rs. 169.50 lakhs
1970-71	...	„ 220.46 „
1971-72	...	„ 271.68 „

(b) To minimise detention of wagons regular co-ordination is maintained with the parties to secure quick release of wagons. In case of detention beyond free time demurrage charges as per rules are levied. The rate of demurrage charges having been enhanced with effect from 1-12-1972, the position with regard to release of wagons is likely to improve considerably.

I The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Bhai Mahavir. t[ ] English translation.

†[**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों श्रौर उपक्रमों से विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल की गयी राशि नीचे दी गयी है :

1969-70	..	169.50 लाख रुपये
1970-71	..	220.46 लाख रुपये
1971-72	..	271.68 लाख रुपये

(ख) माल डिब्बे कम से कम रुकें, इसके लिए पार्टियों के साथ नियमित समन्वय रखा जाता है जिससे कि माल डिब्बों को शीघ्र खाली कराया जा सके। यदि माल डिब्बे छूट समय के बाद रुके रहते हैं तो उन पर नियमानुसार विलम्ब शुल्क लिया जाता है । 1-12-1972 से विलम्ब शुल्क की दर बढ़ जाने से श्राशा है, माल डिब्बों के खाली होने की स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।]

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, यह जो जानकारी मंत्री जी ने दी है इससे प्रकट होता है कि सरकारी क्षेत्र ही सरकारी क्षेत्र के रास्ते का कितना बड़ा रोड़ा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ही सरकार की रेलों को चलाने में कैसी रुकावटें बनते हैं यह श्रापके उत्तर से स्पष्ट है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि यह डिले होने के कारण श्राप भले ही डैमेरेज चार्ज कर लें, लेकिन इससे किसी तरह का समाधान या हल नहीं निकलेगा, कारण यह है कि डैमरेज भी देने के लिए टैक्स पेयर है। पब्लिक सेक्टर को जो लास होगा, जो डैमरेज उसको पे करना पड़ेगा वह किसी इंडिविजुग्रल या प्राइवेट कंसर्न पर नहीं पड़ने वाला है, जिससे कि उन्हें तकलीफ हो। तो पब्लिक एक्सचेकर की कास्ट पर ही पब्लिक सेक्टर की इंएफीशियेंसी पनप रही है। क्या श्राप इस बारे में विचार करेंगे कि यह जो बढ़ता हुश्रा श्रौर इतना भारी लास है डैमरेज के कारण, जो पब्लिक सेक्टर को देना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी कुछ निश्चित श्रधिकारियों पर डाली जाय श्रौर उनको किसी तरह से इसके लिए उत्तरदायी ठहरा कर के कुछ श्रंश में उनको उसका दन्ड भुगतने के लिए मजबूर किय जाय, यह सारा तो श्राप उनसे वसूल नहीं करेंगे, परन्तु श्राप इतना कर सकते हैं कि उनका प्रमोशन, एक्सटेंशन, उनके एलाउंसेस श्रौर बाकी चीजों पर इसके कारण कुछ श्रसर पड़े, इसकी कुछ व्यवस्था हो क्या श्राप इसके बारे में कुछ विचार करेंगे ?

<u>شری محمد شفیع قریشی</u> : شریمن- ریلوے کی همیشه یه کوشش رهی هے که ویگنس جلد سے جلد ریلیز هو جائیں تا که دوسرے لوگوں کے کام آسکیں - جو کنسائنیز هوتے هیں وہ اگر مال چڑانے میں کوتاهی کرتے هیں ویگنس کو وقت پر خالی نہیں کرتے تو یه ٹهیک هے که ان کو اس کا ڈیمریج دینا پڑتا هے اور یه تو منترالیوں کا کام هے یا ان پبلک انڈرٹیکنگس کا کام هے که وہ خود اپنی جگه پر اپنے کرمچاریوں کو هدایت کریں که جونہی ویگنس مال لے کر آئیں ان کو وہ وقت کے اندر خالی کر دیں یا پھر لوڈ کر کے روانه کر دیں - هماری طرف سے برابر اس کے لئے کوشش هوتی رهی هے اور ابهی جو هم نے ٹائم گهٹا دیا هے ویگنس کو خالی کرنے کے لئے اور جو ڈیمریج بڑھا دیا هے اس سے هم کو ویگنس ملنا ضروری نہیں هے لیکن روپیه ضرور ملے گا لیکن اس کے لئے بهی منسٹرس کے ساتهه مل کر کوشش کی جائیگی تا که ویگنس جلد سے جلد فارغ هو سکیں -

‡[**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : श्रीमन्, रेलवे की हमेशा यह कोशिश रही है कि वैगन्स जल्द से जल्द रिलीज हो जाएं ताकि दूसरे लोगों के काम श्रा सकें । जो कंसाइनीज होते हैं, वे श्रगर माल छुड़ाने में कोताई करते हैं वैगन्स को वक्त पर खाली नहीं करते तो यह ठीक है कि उनको उसका

†[ ] Hindi translation.

‡[ ] Hindi transliteration

डेम्रेज देना पड़ता है और यह तो मंत्रालयों का काम है या उन पब्लिक अण्डरटेकिंग्स का काम है कि वह खुद अपनी जगह पर अपने कर्मचारियों को हिदायत करें कि ज्योंही वैगन्स माल लेकर आएं उनको वह वक्त के अन्दर खाली कर दें या फिर लोड करके रवाना कर दें। हमारी तरफ से बराबर उसके लिए कोशिश होती रही है और अभी जो हमने टाइम घटा दिया है वैगन्स को खाली करने के लिए और जो डेम्रेज बढ़ा दिया है, उससे हम को वैगन्स मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन रुपया जरूर मिलेगा लेकिन उसके लिए भी मिनिस्टर्स के साथ मिल कर कोशिश की जायगी ताकि वैगन्स जल्द से जल्द फारिग हो सकें।]

डा॰ भाई महावीर : मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे यह पता लगता है कि सरकार का एक हाथ क्या करता है, दूसरे को उसका पता नहीं और दूसरा हाथ जो है उसे चिन्ता नहीं कि पहला हाथ क्या कर रहा है? मेरा प्रश्न यह था मैं फिर से पूछ रहा हूं कि क्या रेल मंत्री कैबिनेट में भारत सरकार के दूसरे मंत्रियों के सामने यह बात रखेंगे और उनसे कहेंगे कि रेल नेशनल प्रापर्टी है, रेलों को ठीक चलाने के लिए सारे देश की जिम्मेदारी है और सारे मंत्रालयों की जिम्मेदारी है, इसलिए अलग-अलग सरकारी उपक्रमों में रेलवे वैगन्स ज्यादा देर न रुकें इसकी जिम्मेदारी कुछ विशेष अधिकारियों के ऊपर रखने की पद्धति अपनायेंगे, जिससे वह डिस्करेज हों और उनके ऊपर अंकुश लगे और इस प्रकार से बैस्ट यूटिलाइजेशन आफ रनिंग स्टाफ और रोलिंग स्टाफ जो है, इसके बारे में कैबिनेट में निर्णय करवाने की कोशिश करेंगे?]

SHRI T. A. PAI: Sir, 30 to 40 per cent of the demurrage comes from the public sector and it is not a very happy thing. We have raised the demurrage both on the private sector as well as the public sector and reduced the delay in order *to* see that the utilisation of wagons is maximised. We arp trying to see that the difficulties of the public sector are got over by giving them every assistance in returning the wagons to us rather than paying the demurrage. 1 will certainly take it up with my colleagues to see that our wagons are not delayed. We are more interested in getting the wagons utilised rather than collecting the demurrage either from the private sector or public sector.

DR. BHAI MAHAVIR: I am asking pointedly whether you will evolve a system. He is avoiding that question. The persons concerned should be made personally responsible.

SHRI T. A. PAI: We are trying to understand what exactly are the difficulties, to get over those difficulties. We shall certainly get into the area of fixing responsibility for holding the wagons so that any Department of the Government does not pay demurrage to us.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN: The question emphasises the aspect of wagon .movement which leads to a great scarcity of wagons which our country as a whole is experiencing in every Railway Department. May I know from the hon. Minister whether it is a fact that the detention of wagons by industries in the public sector has led to the great wagon shortage that we are experiencing throughout the country which has, in turn, led to increase in prices? Are there other vital factors which are responsible for the shortage of wagons and would the hon. Minister go into them and see that the wagon movement is speeded up?

SHRI T. A. PAI: Sir, there have been many reasons for detention of wagons. The need has gone up and the turn-out of wagons has also increased. Detention of wagons in both the public sector and private sector has also gone up. The conditions in the eastern sector were such that partly there was dislocation of traffic. That also was responsible for holding up the wagons. Every effort is being made *to* bring about the co-ordination of the private sector, he public sector, the customers and the trade to see that the release of wagons is done effectively.

SHRI LOKANATH MISRA: The public sector has been the greatest defaulter. Does the hon. Deputy Minister know what are the reasons for such delays in clearing the wagons? Since they are being made to pay demurrage charges, there must be some reasons behind the delay in the clearance of waguns.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I am getting the demurrage. 1 am not paying it. Those people who are paying, will be able to say better what are the reasons for paying the demurrage.

SHRI T. A. PAI: Most of the demurrage comes from the Hindustan Steel and the reason is that every steel plant has its own method of transport of coal, iron ore and all that. We are now trying to see that uniformity is brought about so that the utilisation of wagons is more effective than what has been possible so far.

DR. BHAI MAHAVIR: How much is paid by Hindustan Steel? . . .

SHRI KRISHAN KANT: Could the hon. Minister give the comparative figures in the private sector and the public sector? How much demurrage is paid by TISCO and how much is paid by the Hindustan Steel? I have got complaints that the private sector undertakings get preferential treatment in the allotment of wagons at local level.

SHRI T. A. PAI: The utilisation of wagons in the private sector is certainly much more efficient. I am prepared to admit wherever there is deficiency. As to how much has been collected from the public sector and which public sector undertaking had brought us more, I have answered it. It is not correct to say that wagons are held up or given on priority to the private sector. In fact, every convenience is provided to the public sector and the deficiencies that have arisen shall certainly be removed.

DR. BHAI MAHAVIR: It is not a socialistic answer, Mr. Pai.

MR. CHAIRMAN: Don't interrupt your colleague.

श्री प्रेम मनोहर : अभी मंत्री महोदय ने स्वयं बताया कि हम डेमरेज और व्हाहरफेज कलेक्ट करने के इंटरेस्ट में नहीं है। हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे वैगन्स जल्दी मूव हों। अभी इसी एक दिसम्बर में हमारी रेलवे मिनिस्ट्री ने ग्राउन्ड रेन्ट 5 रु० से बढ़ा कर 125 रु० पर डे कर दिया है, तो मैं अपने मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वैगन के मामले में तो समझ में आ सकता है कि वैगन के लिए आप डेढ़ सौ, दो सौ, तीन सौ जो चाहें लगा दीजिए, जिससे आपके वैगन्स जल्दी से मूव हों लेकिन इसमें आपका क्या उद्देश्य है कि आपने ग्राउन्ड रेन्ट 5 रु० रोज से बढ़ा कर 125 रु० पहले 3 रोज के लिए और उसके बाद ढाई सौ रुपया रोज कर दिया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या उस ग्राउन्ड रेन्ट बढ़ाने से वैगन मूवमेंट को तेज करने की आपकी कोई योजना है और अगर योजना है तो मैं आपको दृष्टांत दूं...

श्री सभापति : नहीं, अब इसको रहने दीजिए।

श्री प्रेम मनोहर : ... कि जोधपुर डिविजन में मारवाड़ स्टेशन है, वहां डेढ़-डेढ़ महीने वैगन्स नहीं मिले और वहां जो रॉ मैटीरियल बनता है उसके बिना पेपर इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज बन्द हो जाएंगी और यह लेटर है कि 7-11-72 से इंडेन्ट लगे हुए हैं और वैगन्स नहीं मिले तो मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा आपने 5 रु० से बढ़ा कर ग्राउन्ड रेन्ट 125 रु० किया है तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या इन वैगन्स को...

شری محمد شفیع قریشی : جب گاڑی مال لے کر آتی ہے جب ڈبہ آتا ہے تو ٥ گھنٹے کے اندر اگر وہ خالی نہ کرے تو اس کا ڈیمریج لگتا ہے اس کے بعد جب مال اتارا جاتا ہے اس کے

بعد ۲۴ گھنٹے کا فری ٹائم مل جاتا ہے لیکن گراؤنڈ پر بھی مال نہیں اٹھایا جائے گا تو جو مال بھر کر ویگنس آئینگے ان کا سامان اتارنا مشکل ہو جائیگا اس لئے ضروری ہے کہ گراؤنڈ رینٹس بھی بڑھائیں تا کہ مال لینے والے اپنا مال جلدی سے لے جائیں -

† [**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : जब गाड़ी माल ले कर आती है जब डिब्बा आता है तो 5 घंटे के अन्दर अगर वह खाली न करे तो उसे डेमरेज लगता है, उसके बाद जब माल उतारा जाता है उसके बाद 24 घंटे का फ्री टाइम मिल जाता है, लेकिन ग्राउन्ड पर भी माल नहीं उठाया जायगा तो जो माल भर कर वैगन्स आएंगे उनका सामान उतारना मुश्किल हो जायगा. इसलिये जरूरी है कि ग्राउन्ड रेंट्स भी बढ़ा ताकि माल लेने वाले अपना माल जल्दी से ले जायें।]

श्री प्रेम मनोहर : कितना तक बढ़ाएंगे? 5 रु० से 125 रु० तक बढ़ा दिया है आपने।

MR. CHAIRMAN: No please. You are merely repeating. I won't allow this Next question.

710. *[The questioner (Shri Siiuram Kesri) was absent. For answer* vide *col.* 40-41 infra.]

IRRIGATED LAND IN RAJASTHAN

"711. SHRIMATI LAKSHMI KUMARI CHUNDAWAT; Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the acreage of irrigated land at present in Rajasthan, District-wise; and

(b) the acreage of land likely to be irrigated by the end of the Fourth Plan period?

j[ ] Hindi transliteration.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJNATH KUREEL): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) A statement showing the district-: wise irrigated area (gross) in Rajasthan for I 1969-70, the latest year for which it is I available at the Centre is attached.

(b) It is anticipated by the State Gov ernment that the gross irrigated area at the end of the Fourth Plan in Rajasthan would be about 28.6 lakh hec. District?wise break up is not available.

STATEMENT

District	*Gross Irrigated area (in Hectares)*
Ajmer	96,392
Alwar	102,020
Banswara	13,604
Barmer	16,419
Bharatpur	161,472
Bhilwara	163,160
Bikaner	248
Bundi	103,932
Chittor	109,953
Churu	369
Dungarpur	13,915
Ganganagar	635,353
Jaipur	243,079
Jaisalmer	270
Jalore	78,453
Jhalawar	33,540
Jhunjhunu	19,797
Jodhpur	30,437
Kota	132,378
Nagaur	28,544
Pali	74,596
S. Madhopur	105,196
Sikar	48,515
Sirohi	37,043
Tonk	73,992
Udaipur	96,720
TOTAL (1969-70)	2,419,397